

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 37/2015, जी.सी.एम.एस. नं. 2015/00222

1. हरफूल पुत्र भुल्लन
2. धनपाल
3. बंटी
4. सोनू
5. लोहबा पत्नि हरफूल
6. गुड्डी बेवा बृसभान

समस्त जातियान मालीयान निवासीयान चन्देती
तहसील मण्डरायल जिला करौली, राज0।



अपी0

बनाम

1. हेमराज पुत्र किशनली
2. रामवीर पुत्र किशनली
3. वासुदेव पुत्र किशनली नाबालिक जरिए संरक्षक माता लोडी
4. प्रभो } पुत्रीयान किशनली नाबालिक जरिये संरक्षक माता लोडो
5. रामबाई }
6. गिल्लू } पिसरान गुटई जातियान मालीयान निवासीयान चन्देती तहसील,
7. मिश्री } मण्डरायल जिला करौली, राज0।
8. जगनली }
9. लोडो बेवा किशनली
10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डरायल

रेस्पो0

(अपील विरुद्ध निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर, मण्डरायल
मु0न0 33/09 निर्णय व डिग्री दिनांक 29.11.11)

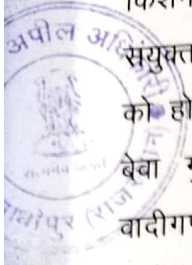
उपस्थित अभिभाषक

1. अपी0 की ओर से श्री लियाकत अली व श्याम मोहन शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से श्री दिनेश कुमार बंसल

निर्णय

दिनांक 29.12.2021

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 33/09 निर्णय डिग्री दिनांक 29.11.2011 उनवानी हेमराज वगै0 बनाम हरफूल वगै0 के विरुद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में



29.12.2019
अपील प्राधिकरण
सवाई माधोदास

वादी/रेस्पो. ने वादपत्र 88, 188 आर0टी0एक्ट0 इस आशय का पेश किया कि आराजी ख.नं. 247 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा, ख.नं. 249 रकबा 4 बीघा 10 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 14 विस्वा ग्राम चन्देली तहसील मण्डरायल में स्थित है। उक्त विवादित आराजी वादी/रेस्पो. 1 ल0 5 के पिता व वादी नं. 6/रेस्पो. सं. 9 के पति किशनली पुत्र गुटई व वादी नं. 7 ल0 9/रेस्पो. सं. 6 ल0 8 व सोमोती बेवा गुटई कि संगुस्त खातेदारी व कब्जे की आराजी है। किशनली का स्वर्गवास दिनांक 11.08.2009 को हो चुका है। मृतक किशनली के वारिसान वादीगण सं. 1 ल0 6 है और सोमोती बेवा गुटई का स्वर्गवास दिनांक 20.05.2007 को हो चुका है। उसके वारिसान वादीगण/रेस्पो. सं. 1 ल0 9 है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी वादीगण/रेस्पो. के खातेदारी व कब्जे काशत की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में रौधई से चन्देली तक जाने वाली सडक का निर्माण पी.डब्लू.डी विभाग ने कराया है जिसकी मुआवजा राशि वादीगण/रेस्पो. ने प्राप्त की है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण/अपी0 का कोई सम्बंध व ताल्लुक वास्ता नहीं है। प्रतिवादीगण/अपी0 ताकतवर व पैसे वाले व्यक्ति है। वादीगण/रेस्पो. गरीब व कमजोर किस्म के व्यक्ति है। प्रतिवादीगण/अपी0 उक्त विवादित आराजी को वादीगण/रेस्पो. से ताकत व पैसे के बल पर छीनने पर आमादा है। दिनांक 15.11.2009 को प्रतिवादीगण/अपी0 विवादित आराजीयात पर आ गये और वादीगण/रेस्पो. से झगडा फसाद करने पर आमादा हो गये। वादीगण/रेस्पो. ने प्रतिवादीगण/अपी0 से कहा की उक्त विवादित आराजीयात हम वादीगण/रेस्पो. की खातेदारी व कब्जे की आराजीयात है और हम वादीगण/रेस्पो. ही उक्त विवादित आराजीयात को हमेशा से काशत करते चले आ रहे है। इस बात पर प्रतिवादीगण/अपी0 नाराज हो गये और बैलों को हल में से खोल कर भगा दिया और वादीगण/रेस्पो. को फसल काशत नहीं करने देने की धमकी देने लगे। प्रतिवादीगण/अपी0 की इस अनाधिकार कार्यवाही से वादीगण/रेस्पो. पर भारी आघात होगा। वादीगण/रेस्पो. अपने खातेदारी व कब्जे काशत की आराजीयात के काशत से बंछित हो जावेगें। वादीगण/रेस्पो. के भरण पोषण का मुख्य जरिया कृषि भूमि की उपज है। यदि प्रतिवादीगण/अपी0 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो वादीगण/रेस्पो. को अपूर्णनीय क्षति व भारी असुविधा होगी। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि वादीगण/रेस्पो. को उक्त विवादित आराजी का खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण/अपी0 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण/रेस्पो. की कब्जे काशत व खातेदारी की आराजीयात में कोई रूकावट पैदा न करें और न ही किसी दीगर व्यक्ति से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो. द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो. का दावा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपी0 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंड को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.11 अधिनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून रूहेदाद मिसिल है और विधि विरुद्ध है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जो तनकीयात दावे एवं जबाव दावे के आधार पर बनायी गई है वो विधि अनुरूप नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न नजीरों में स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि वादपत्र का निर्णय किए जाते वक्त प्रत्येक तनकी पर दावे एवं जबाव दावे के आधार पर पत्रावली में उपस्थित दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की तुलना कर प्रत्येक तनकी पर अपना मत पृथक-पृथक पारित करना चाहिये परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में उक्त प्रकरण का एक साथ निर्णय व डिक्री पारित कर कानूनी भूल की है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। उक्त वर्णित विवादित आराजीयात पर रेस्पों. का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है और रेस्पों. द्वारा धारा 88 के तहत वादपत्र पेश किया है। कब्जे के अभाव में धारा 88 आर. टी.एक्ट के तहत वादपत्र मंटेवल नहीं है। उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने अपी0 का बेदखल किए जाने के आदेश पारित किये है जबकि रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत वादपत्र धारा 88 के तहत था, बेदखली का कोई वादपत्र रेस्पों. द्वारा पेश नहीं किया गया है। रेस्पों. मूल गांव से डेढ किलोमीटर रावरे नामक स्थान पर रहते है तथा अपी0 का खसरा नं. 364/1 वाके ग्राम चन्देली पर कब्जा है जो करीब 40-50 साल पुराना है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादपत्र में दिनांक 18.11.11 को धारा 88 के अनुतोष को डिलीट किया है, वह भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया है। वगैर घोषणा के अभाव में रेस्पों. को खातेदारी नहीं मिल सकती है और दौराने दावा यदि किसी प्रकार की कोई खातेदारी रेस्पों. ने प्राप्त की है तो उसकी कोई महत्वता नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री एकपक्षीय कार्यवाही कर पारित की है। अपी0 को साक्ष्य सुनवायी का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपी0 को दिनांक 02.06.2015 तक नहीं थी। दिनांक 02.06.2015 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर अपी0 से यह कहने पर हुयी कि तुम्हारे खिलाफ कोर्ट का फैसला हो गया है तुम तुम्हारी पाटोल हटा लो। इस पर दिनांक 04.06.2015 को उक्त निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त की। इससे पूर्व अपी0 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। अपी0 द्वारा अपील पेश करने तक का समय क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जावें। इस प्रकार उक्त निर्णय का ज्ञान अपीलार्थी को हो सका। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

4. रेषों. के विद्वान अधिवक्ता ने अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि उक्त विवादित आराजी रेषों. 1 ल0 5 के पिता व रेषों. सं. 9 के पति किशनली पुत्र गुटई व रेषों. सं. 6 ल0 8 व सोमोती बेवा गुटई के संयुक्त खातेदारी व कब्जे की आराजी है। किशनली का स्वर्गवास दिनांक 11.08.2009 को हो चुका है। मृतक किशनली के वारिसान रेषों. सं. 1 ल0 5 व 9 है, और सोमोती बेवा गुटई का स्वर्गवास दिनांक 20.05.2007 को हो चुका है। उसके वारिसान रेषों. सं. 1 ल0 9 है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी रेषों. के खातेदारी व कब्जे काशत की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में रौधई से चन्देली तक जाने वाली सडक का निर्माण पी.डब्लू.डी विभाग ने कराया है जिसकी मुआवजा राशि रेषों. ने प्राप्त की है। उक्त विवादित आराजी से अपी0 का कोई सम्बंध व ताल्लुक वास्ता नहीं है। अपी0 ताकतवर व पैसे वाले व्यक्ति है। रेषों. गरीब व कमजोर किस्म के व्यक्ति है। अपी0 उक्त विवादित आराजी को रेषों. से ताकत व पैसे के बल पर छीनने पर आमादा है। दिनांक 15.11.2009 को अपी0 विवादित आराजीयात पर आ गये और रेषों. से झगडा फसाद करने पर आमादा हो गये। रेषों. ने अपी0 से कहा की उक्त विवादित आराजीयात हम रेषों. की खातेदारी व कब्जे की आराजीयात है और हम रेषों. ही उक्त विवादित आराजीयात को हमेशा से काशत करते चले आ रहे है। इस बात से अपी0 नाराज हो गये और बैलों को हल में से खोल कर भगा दिया और रेषों. को फसल काशत नहीं करने देने की धमकी देने लगे। अपी0 की इस अनाधिकार कार्यवाही से रेषों. पर भारी आघात होगा। रेषों. अपने खातेदारी व कब्जे काशत की आराजीयात के काशत से बंछित हो जावेगें। रेषों. के भरण पोषण का मुख्य जरिया कृषि भूमि की उपज है। यदि अपी0 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो रेषों. को अपूर्णनीय क्षति व भारी असुविधा होगी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपी0 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होते हुए भी जानबूझ कर अपील देशी से पेश की है। परिसीमन अधिनियम की धारा-5 के बारे में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 खारिज फरमाया जावे। अतः अपी0 की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

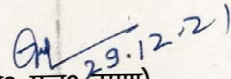
5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी सम्बत् 2066-69 वाके ग्राम चन्देली तहसील मण्डरायल के खतौनी सं. 09 पर ख.नं. 247 व 249 किशनली, गिल्लू, मिश्री, जगनली पि0 गुटई सोमोती बेवा गुटई जाति माली सा.देह राहिन किशनली का हिस्सा बैंक ऑफ

बडौदा शाखा मण्डरायल दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी सं. 1 ल0 6 की ओर से जवाब दावा दिनांक 02.07.2010 के मद सं. 1 में प्रतिवादी सं. 1 ल0 6 का विवादित भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं होना अंकित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.11 को ख.नं. 247 व 249 के बाबत आदेश पारित किया है यह आदेश विधि संगत है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांत सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर मण्डरायल के मु0नं0 33/2009 निर्णय दिनांक 29.11.2011 को यथावत रखा जाता है।
9. निर्णय आज दिनांक 29.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।


(बी0 एल0 रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर